



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257119
CG-DL-E-12092024-257119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3583]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3583]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3918(अ).—यतः, मै. विपरो लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट नंबर -2, एमआईडीसी, फेज़-1, हिंजेवाडी, मुलशी तालुका, पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3025 (अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2017 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में 9.15 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. विपरो लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 9.15 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र संख्या एसईजेड-2017/सीआर-14/आईएनडी-2 दिनांक 6 नवंबर, 2023 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और भूमि का टुकड़ा राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 9.15 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/12/2017-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 3918(E).—Whereas, M/s. Wipro Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No.2, MIDC, Phase1, Hinjawadi, Mulshi, Taluka, Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 9.15 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3025 (E) dated 11.09.2017;

AND, WHEREAS, M/s. Wipro Limited has now proposed to de-notify the entire area of 9.15 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. SEZ-2017/CR-14/Ind-2 dated 6th November, 2023. After de-notification, the land parcel will be utilized toward creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged and the parcel of land will conform to land use guidelines/ master plan of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 9.15 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/12/2017-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.